दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सिविल वाद (मूल पक्ष) 2840/2011

निर्णय तिथि : 10.03.2014

मैसर्स जीई कैपिटल सर्विसेज इंडिया वादी

द्वारा: श्री गौरव गौर, अधिवक्ता

बनाम

प्रशांत घोष एवं अन्य बी+ प्रतिवादीगण

द्वारा: प्रतिवादीगण हेतु श्री अनिरुद्ध
देशमुख और श्री अनिरुद्ध राजपूत,
अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी

न्या. जी.एस. सिस्तानी (मौखिक)

अं.आ. 13599/2013

1. यह प्रतिवादीगण द्वारा दायर एक आवेदन है जिसमें अं.आ. 13598/2013 को पुनः दाखिल करने में 430 दिनों के विलंब को माफ करने की मांग की गई है।
2. आवेदन में बताए गए कारणों और दिनांक 23.1.2014 को इस न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष वादी/गैर-आवेदक के अधिवक्ता द्वारा

उठाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए कि वह वर्तमान आवेदन का विरोध नहीं करना चाहते हैं, इस आवेदन को अनुमति दी जाती है। अं.आ. 13598/2013 को पुनः दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जाता है। अं.आ. 13598/2013 को अभिलेख पर लिया जाए।

3. आवेदन का निपटान किया जाता है।

अं.आ. 13598/2013

4. वर्तमान आवेदन प्रतिवादीगण द्वारा सि.प्र.स. के आदेश XXXVII नियम 3(5) के तहत दायर किया गया है, जिसमें वर्तमान वाद में बचाव के लिए अनुमति मांगी गई है, जिसे सि.प्र.स. के आदेश XXXVII के प्रावधानों के तहत दायर किया गया है।
5. वादपत्र के अनुसार, प्रतिवादी सं. 1 ने वित्तीय सहायता के लिए वादी से संपर्क किया था। प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादी सं. 1 द्वारा देय सभी और हर राशि के उचित पुनर्भुगतान के लिए वादी के पक्ष में दिनांक 23.5.2004 को एक व्यक्तिगत गारंटी निष्पादित की।
6. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि वादपत्र में कहा गया है, यह है कि प्रतिवादी सं. 1 ने वाणिज्यिक उद्देश्यों में उपयोग के लिए कुछ चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए वित्त प्राप्त करने के लिए मई, 2004 के आसपास वादी से संपर्क किया था। प्रतिवादीगण द्वारा दिए गए

अभ्यावेदन और आश्वासनों पर भरोसा करते हुए, वादी ने प्रतिवादीगण के साथ निम्नलिखित उपकरण मास्टर सुरक्षा और ऋण समझौता सं. दर्ज कीं:

- i) पुरानी सं. W11293 (नयी सं. AI20643), दिनांक 23 मई-2004।
- ii) पुरानी सं. W11283 (नयी सं. AI20634) दिनांक 23 मई-2004।
- iii) पुरानी सं. W11283 (A) (नयी सं. A120635) दिनांक 23 मई-2004। (इसके बाद "समझौता" रूप में संदर्भित)

7. उक्त ऋण के संबंध में दस्तावेजों, संवितरण, वसूली आदि से संबंधित सभी मामलों में प्रतिवादी(गण) द्वारा उक्त समझौते की शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया।
8. इसके अलावा, वादपत्र के अनुसार, समझौते पर बातचीत, विचार-विमर्श, निष्कर्ष और निष्पादन नई दिल्ली में किया गया था। वादी ने दिल्ली से उक्त ऋण राशि स्वीकृत और वितरित की। ऋण समझौते के अनुसार, प्रतिवादी सं. 1 को 20.00 लाख रुपये का वित्तपोषण किया गया था, जिसका उपयोग अन्य बातों के अलावा, चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए किया गया था, जैसे कि एक लॉजिक 3 प्रो अल्ट्रासाउंड स्कैनर और उसके सहायक उपकरण, एक जीई डीएक्स 200 चिकित्सा निदान इमेजिंग उपकरण और एक 24 चैनल डिजिटल ईईजी मशीन मॉडल एनपी

2400पी/डिजिटल ईएमजी मशीन मॉडल एनपी 2300 और स्पिरोविन स्पिरोमेट्री मशीन। उक्त अवधि ऋण दिनांक 23.5.2004 के समझौते में निहित और सहमत नियमों और शर्तों पर स्वीकृत किया गया था।

9. इसके अलावा, समझौते की शर्तों के अनुसार, वादी कंपनी द्वारा वितरित ऋण राशि निम्नलिखित तरीके से चुकाई जानी थी:

विवरण	पुरानी सं. W11293 (नयी सं. AI 20643)	पुरानी सं. W11283 (नयी सं. AI 20634)	पुरानी सं. W11283 (नयी सं. AI20635)
प्रधानाचार्य राशि	5,20,000/- रुपये	11,36,000/- रुपये	3,44,000/- रुपये
अवधि/ईएमआई	60 ईएमआई	60 ईएमआई	60 ईएमआई
ब्याज की दर	11.00%	11.00%	11.00%
प्रथम किस्त की देय तिथि	07.07.2004	27.06.2004	27.06.2004

10. डिफॉल्ट/देरी की स्थिति में प्रतिवादी 36% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। प्रतिवादी सं. 1 ने पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए, जिसमें समझौते के अनुसार ब्याज भुगतान और मूल राशि का आंशिक भुगतान शामिल था।

11. ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार यह भी सहमति हुई थी कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निर्धारित समय पर ऋण राशि की किसी किस्त का भुगतान करने में चूक होने की स्थिति में, सावधि ऋण की पूरी राशि या उस समय देय शेष राशि, जिसमें बकाया दंडात्मक ब्याज भी शामिल है, तत्काल देय हो जाएगी और प्रतिवादी सं. 1 को चुकानी होगी। ऋण के लिए सुरक्षा और उसके उचित पुनर्भुगतान पर विचार करते हुए और सुरक्षा के रूप में, प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 23.5.2004 को वादी के पक्ष में चिकित्सा उपकरणों को संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया पहला शुल्क बनाया था। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी सं. 1 ने, स्वामी के रूप में, वादी के पक्ष में दिनांक 23.5.2004 को मांग वचन पत्र भी निष्पादित किया, जिसके द्वारा वादी को मांग पर 11% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 20.00 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने की अपनी देयता को स्वीकार किया। वचन पत्र में प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया और बिना शर्त वादा किया कि वह विलंबित भुगतान पर 36% प्रति वर्ष की दर से, चूक की गई राशि पर लागू ब्याज दर के अतिरिक्त, भुगतान करेगा, जब तक कि राशि की वसूली नहीं हो जाती।
12. वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को दिए गए सावधि ऋण को और अधिक सुरक्षित करने के लिए, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 23.5.2004 को

एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त व्यक्तिगत गारंटी निष्पादित की गई थी। प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के पक्ष में दिनांक 23.5.2004 को एक मांग वचन पत्र भी निष्पादित किया, जिसमें वादी को मांग पर 20.00 लाख रुपये की राशि 11% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने की अपनी देयता को स्वीकार किया। वचन पत्र में, प्रतिवादी सं. 1 ने भी स्वीकार किया और बिना शर्त वादा किया कि वह 36% प्रति वर्ष की दर से विलंबित भुगतान शुल्क का भुगतान करेगा, जो कि चूक की गई राशि पर लागू ब्याज दर के अतिरिक्त होगा, जब तक कि इसकी वसूली नहीं हो जाती।

13. ऋण समझौते के अनुसार ऋण, ब्याज और अन्य सभी शुल्कों के उचित पुनर्भुगतान के लिए प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दिनांक 23.5.2004 की एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त व्यक्तिगत गारंटी भी निष्पादित की गई थी। प्रतिवादी सं. 2 ने वादी के पक्ष में दिनांक 23.5.2004 की तारीख का मांग वचन पत्र भी निष्पादित किया, जिसमें वादी को मांग पर 20.00 लाख रुपये की राशि 11% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने की अपनी देयता को स्वीकार किया। वचन पत्र में प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है और बिना शर्त वादा किया है कि वे वसूली होने तक चूक की गई राशि पर लागू ब्याज दर के अलावा 36% प्रति वर्ष की दर से विलंब भुगतान शुल्क का भुगतान करेंगे। वादी का यह भी मामला है

कि ऋण वितरित होने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा केवल कुछ किशतों का भुगतान किया गया था।

14. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रतिवादी मुख्य रूप से इस आधार पर बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति चाहते हैं कि, सबसे पहले, इस न्यायालय के पास वर्तमान वाद पर विचार करने और विचार करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वादी द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों पर भरोसा किया, जो दिखाते हैं कि स्टाम्प पेपर कर्नाटक में खरीदे गए थे। अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि प्रतिवादीगण का यह भी मामला है कि प्रतिवादीगण ने पश्चिम बंगाल में ऋण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे और इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता में कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए समझौते का खंड 10(छ), इस न्यायालय को अधिकारिता प्रदान नहीं कर सकता है।
15. वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि चूंकि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में किए गए थे, ऋण का वितरण नई दिल्ली से किया गया था, वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे और भुगतान भी नई दिल्ली में ही किया जाना था, तथा किशतें भी नई दिल्ली में ही देय थीं, इसलिए इस न्यायालय को इस मामले पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है।

16. अपने कथन के समर्थन में वादी के अधिवक्ता ने **जी.ई. कैपिटल सर्विसेज इंडिया बनाम जी. न्यूरोमेड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 2007** (98) डी.आर.जे. 74, विशेष रूप से पैरा 14, 16 से 18 पर भरोसा किया है, जो इस प्रकार है:

14. एल.एन. गुप्ता एवं अन्य बनाम श्रीमती तारा मणि (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय ने कहा था:

धारा 20, खंड (ग), सि.प्र.स. के तहत, एक वाद उस न्यायालय में दायर किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता में कार्रवाई का कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है। अनुबंध के पूर्ण या आंशिक रूप से निष्पादन का स्थान और इसलिए, भुगतान या आंशिक भुगतान का स्थान उस स्थान पर कार्रवाई के कारण को जन्म देगा। ऐसा स्थान अनुबंध करते समय निर्दिष्ट किया जा सकता है, बाद में नियुक्त किया जा सकता है, या निहित हो सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, धारा 47, 48 और 49 निष्पादन के स्थान से संबंधित हैं। जहां तक निर्धारित स्थान का संबंध है, आमतौर पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

16. यदि यह मान भी लिया जाए कि ऋण समझौता कानपुर में निष्पादित किया गया था (हालांकि वादी द्वारा इस तथ्य पर विवाद किया गया है), तो मामले का तथ्य यह है कि ऋण समझौते में ही कहा गया है कि दिल्ली के न्यायालयों को विशेष अधिकारिता प्राप्त होगी।

17. मुझे वादी के इस तर्क में दम नज़र आता है कि यह मामला किसी ऐसे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने का नहीं है,

जिसके पास अन्यथा कोई अधिकारिता नहीं है। इस न्यायालय के पास वर्तमान वाद पर विचार करने की अधिकारिता है, क्योंकि ऋण दिल्ली में चुकाया जाना था। यह बात ऋण समझौते को पढ़ने और प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा निष्पादित वचन-पत्रों से स्पष्ट है। वचन पत्र प्रतिवादीगण द्वारा ऋण समझौते की शर्तों के अनुसरण में निष्पादित किए गए हैं, और वे इससे स्वतंत्र नहीं हैं। प्रतिवादीगण का यह मामला नहीं है कि वचन पत्र के तहत प्रतिवादीगण की देनदारी ऋण समझौते के तहत उनकी देनदारी के अतिरिक्त है। ऋण समझौते को वचन पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए। भले ही ऋण समझौते में यह नहीं लिखा है कि इसे दिल्ली में या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान पर चुकाया जाना है, वचन पत्र के साथ इसे पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि ऋण की अदायगी दिल्ली में होनी थी। अन्यथा भी यह तय है कि ऋणदाता को ढूंढना देनदार का काम है। एल.एन. गुप्ता (पूर्वोक्त) देखें ऋण समझौता अपने आप में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से यह प्रावधान नहीं करता है कि ऋण की अदायगी लखनऊ में या दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर होगी। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त कानूनी सिद्धांत लागू होगा कि ऋण उस स्थान पर चुकाया जाना चाहिए जहां वादी का मुख्य व्यवसाय स्थान है, अर्थात् दिल्ली में होना चाहिए।

18. पक्षकारगण को इस न्यायालय में स्पष्ट रूप से सीमित अधिकारिता प्राप्त है, जो अन्यथा भी उनके पास है।”

17. वादी के अधिवक्ता ने मेसर्स **जीई कैपिटल सर्विसेज इंडिया बनाम डॉ. मोहन चतुभुज जामवार एवं अन्य**, सिविल वाद(मूल पक्ष)2031/2011,

दिनांक 1.7.2013 को निर्णीत, विशेष रूप से पैरा 5, 6 और 8 पर भरोसा किया है, जो इस प्रकार है:

5. वादी और प्रतिवादी सं. 1 के बीच दिनांक 31.01.2007 को हुआ समझौता, जिसके निष्पादन से इनकार नहीं किया गया है, उसके विवरण में कहीं भी यह दर्ज नहीं है कि प्रतिवादी सं. 1 ने वादी द्वारा मशीन की गुणवत्ता या प्रदर्शन के संबंध में किसी प्रतिनिधित्व के कारण वादी से वित्त पर मशीन खरीदने पर सहमति व्यक्त की है; बल्कि उक्त समझौते में कहीं भी मेसर्स बाउश एंड लॉम्ब का उल्लेख नहीं है तथा केवल उस मशीन का वर्णन है जिसे इसके अंतर्गत वित्तपोषित किया गया है; इसी प्रकार यह वादी से यह अपेक्षा नहीं करता है कि चूक होने पर वह मशीन को वापस अपने कब्जे में लेकर या बेचकर देय धनराशि वसूलने का पहला प्रयास करे तथा इसके बजाय वादी को मशीन को वापस अपने कब्जे में लिए या बेचे बिना देय धनराशि को तुरंत वसूलने का अधिकार देता है। शिक्षित वाणिज्यिक व्यक्तियों के बीच लिखित रूप में इस तरह के समझौते के मामले में (जैसा कि सत्येंद्र जैन बनाम मेसर्स ओमवे बिल्डस्टेट प्राइवेट लिमिटेड 199 (2013) डीएलटी 710 और सिविल वाद (मूल पक्ष) सं. 1480/2009 में केमिकल सिस्टम टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम सिंभावली शुगर मिल्स लिमिटेड में 1 फरवरी, 2013 के निर्णय में चर्चा की गई है) इसके उल्लंघन के आधार पर छुट्टी नहीं दी जा सकती है।

6. जहां तक प्रादेशिक अधिकारिता पर आपत्ति का सवाल है, प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित किए गए समझौते के खंड 10(छ) में दिल्ली में वादी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इसके निष्पादन को दर्ज

किया गया है; बचाव की अनुमति के लिए आवेदन में उक्त तथ्य का कोई उल्लंघन नहीं है; इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली में कार्यवाही के कारण का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसके लिए पक्षकारगण के बीच दिनांक 31.01.2007 के समझौते में भी दिल्ली के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के बारे में सहमति शामिल है। इतना ही नहीं, समझौते में वादी का पता केवल दिल्ली का है और वादी का यह सिद्धांत सही है कि देनदार को मामले पर दिल्ली के न्यायालयों को प्रादेशिक अधिकारिता प्रदान करने के लिए ऋणदाता से अनुरोध करना चाहिए। इसी तरह, प्रतिवादी सं. 2 ने भी दिल्ली में वादी को व्यक्तिगत गारंटी दी है और इस प्रकार दिल्ली में वादी को इसके तहत भुगतान करने का वचन दिया है। इस प्रकार इस न्यायालय के दोनों प्रतिवादीगण द्वारा प्रादेशिक अधिकारिता के अभाव के आधार पर लगाए गए तर्कों में कोई दम नहीं है।

8. प्रतिवादी सं. 1 और 2 द्वारा दावा किया गया कि दावा समय-सीमा द्वारा वर्जित है, इसमें भी कोई दम नहीं है। समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख कोई प्रासंगिकता नहीं रखती। बचाव के लिए अनुमति के लिए आवेदन में प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 1.20 करोड़ रुपये का ऋण फरवरी, 2007 से शुरू होकर जनवरी, 2012 तक 60 किस्तों में चुकाया जाना है; इसमें कोई विवाद नहीं है कि किस्तों का भुगतान दिसंबर, 2008 तक किया गया था। वाद उसके तीन साल के भीतर दिनांक 12.08.2011 को दायर किया गया है।

18. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने इस कथन के समर्थन में कि इस न्यायालय के पास प्रादेशिक अधिकारिता नहीं है, *नेशनल हॉर्टिकल्चर*

बोर्ड बनाम मेसर्स फ्लोरा कॉन्टिनेंटल लिमिटेड एवं अन्य, दिनांक 2004
आई एडी (दिल्ली) 81, विशेष रूप से पैरा 11 का हवाला दिया है, जो
इस प्रकार है:

11. लेकिन बचाव के लिए अनुमति के लिए इस आवेदन में आवेदकों ने यह भी तर्क दिया है कि इस न्यायालय के पास कोई क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 ने पहले ही अपना पंजीकृत कार्यालय पुष्पांजलि, दिल्ली से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित कर दिया था और वाद दायर करने के समय प्रतिवादी न तो व्यवसाय कर रहा था और न ही इस न्यायालय की अधिकारिता में लाभ के लिए काम कर रहा था। बेशक ऋण समझौता, वचन पत्र, वचनबद्धता और अन्य दस्तावेज प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा हरियाणा राज्य में निष्पादित किए गए थे। परियोजना का कोई भी हिस्सा दिल्ली में निष्पादित नहीं किया जाना था। वादी की ओर से पेश किया गया तर्क यह है कि पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली से हरियाणा में स्थानांतरित करने की कोई सूचना वादी को नहीं दी गई थी, इसलिए, प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने एक सद्भावनापूर्ण बचाव प्रस्तुत किया है जिसे उनके द्वारा परीक्षण में स्थापित किया जा सकता है।

19. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने **जीई कैपिटल सर्विसेज इंडिया बनाम मे फ्लावर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड**, सिविल वाद (मूल पक्ष) 2859/2011, दिनांक 31.8.2012 को तय किए गए मामले पर भरोसा किया है। अधिवक्ता ने **राष्ट्रीय महिला कोष बनाम द डेल व्यू और अन्य**, 2007

(95) डीआरजे 418, विशेष रूप से पैरा 15 और 16 पर भी भरोसा किया है, जो इस प्रकार है:

“15. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद, मुझे लगता है कि वर्तमान वाद समझौतों, गारंटी विलेखों और प्रोनोट्स पर आधारित है, जिन्हें प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित किया गया था। दस्तावेजों को स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया है और केरल में प्राप्त किया गया है। ये दस्तावेज भी प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि उन्हें केरल में निष्पादित किया गया है। वादी द्वारा जिन प्रोनोट्स और गारंटी विलेखों पर भरोसा किया गया है, वे भी दर्शाते हैं कि उन पर प्रतिवादीगण द्वारा केरल में हस्ताक्षर किए गए हैं। वादी द्वारा किए गए भुगतान निस्संदेह बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किए गए हैं। बैंक ड्राफ्ट की प्रतियां जो अभिलेख में रखी गई हैं, वे दर्शाती हैं कि बैंक ड्राफ्ट केरल में देय हैं। इसलिए, जहां तक वादी के इस तर्क का संबंध है कि ये दस्तावेज दिल्ली में निष्पादित किए गए थे, वही मामला है जिसे केवल दस्तावेजों की जांच करके तय नहीं किया जा सकता है, बल्कि संबंधित तर्कों के समर्थन में साक्ष्य की आवश्यकता होगी। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि वादी की योजना के अनुसार केरल में माइक्रो-फाइनेंस की जरूरत वाली गरीब महिलाओं को ऋण जारी किए गए हैं।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निष्पादित दिनांक 12 अक्टूबर, 1994 के समझौते में कहा गया था कि बकाया राशि पर ब्याज वैसा ही होगा जैसा कि सुविधा के स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट किया गया था। ऋण की राशि दिनांक 30 सितंबर, 1994 के पत्र द्वारा स्वीकृत की गई थी, जिसमें वादी द्वारा ली जाने वाली

ब्याज दर 8% प्रति वर्ष थी। वादी ने प्रतिवादीगण पर दिनांक 19 सितंबर, 2003 के अपने कानूनी नोटिस द्वारा की गई मांग पर वाद का दावा आधारित किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा ऋण राशि का पुनर्भुगतान त्रैमासिक दरों के साथ 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वादी को किया जाना था। वाद का दावा ब्याज की ऐसी गणना पर आधारित है। मुझे लगता है कि वाद में वाद दायर करने की तारीख से 16% प्रति वर्ष की दर से भविष्य के ब्याज की मांग के लिए एक प्रार्थना भी शामिल है।”

20. मुझे प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क में कोई दम नहीं लगता, क्योंकि यह मानते हुए भी कि ऋण समझौते पर दिल्ली में हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, यह विवाद का विषय नहीं है कि ऋण राशि दिल्ली में चुकाई जानी थी, जो कि संबंधित दस्तावेज़ को पढ़ने से स्पष्ट है। इसके अलावा, चूंकि भुगतान दिल्ली में किए जाने थे, इसलिए अनुबंध के पूर्ण या आंशिक निष्पादन का स्थान दिल्ली में है, इसलिए भुगतान का स्थान या कोई भी भाग उस स्थान पर कार्रवाई का कारण बनेगा। इसके अलावा, पक्षकारगण ने दिल्ली के न्यायालयों की अधिकारिता देने पर सहमति व्यक्त की है। यह न्यायालय इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि ऋण समझौते की शर्तों के अनुसरण में प्रतिवादीगण द्वारा वचन पत्र निष्पादित किए गए थे और ऋण समझौते को पढ़ने से पता चलता है कि राशि दिल्ली में चुकाई जानी थी।

21. ऋण समझौते को पढ़ने पर यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि पक्षों ने स्पष्ट रूप से इस न्यायालय को अधिकारिता प्रदान की है, जो अन्यथा भी है। इस न्यायालय के तीन एकल न्यायाधीशों ने समान मामलों से निपटते हुए माना है कि दिल्ली के न्यायालयों के पास इस मामले में अधिकारिता होगी। मेरे पास इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है।
22. प्रतिवादीगण द्वारा इस आवेदन में दूसरा आधार यह बताया गया है कि वचन पत्र में देय परिसमाप्त ऋण का उल्लेख नहीं है और खातों का विवरण, जिस पर वादी द्वारा भरोसा किया जाना है, प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और, इस प्रकार, परिसमाप्त ऋण की अनुपस्थिति में, सि.प्र.स के आदेश XXXVII के प्रावधानों के तहत वाद कायम नहीं रखा जा सकेगा।
23. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि कोई परिसमाप्त ऋण नहीं है क्योंकि खातों के विवरण पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और न ही वचन पत्र में परिसमाप्त ऋण है। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में, यह एक विचारणीय मुद्दा है, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ प्रतिवादीगण को बचाव के लिए सशर्त अनुमति दी जानी चाहिए।

24. तदनुसार, वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाता है, बशर्ते कि प्रतिवादी आज से छह सप्ताह के भीतर वाद की राशि का 50% यानी 35,96,810/- रुपए इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करवा दें, यह राशि एक सावधि जमा में रखी जाएगी, जिसे इस न्यायालय के अगले आदेश तक समय-समय पर नवीनीकृत किया जाएगा। यदि आज पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो वाद वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के खिलाफ 35,96,810 रुपए की राशि के साथ लंबित अवधि और भविष्य में 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित तय माना जाएगा।

25. आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

सिविल वाद (मूल पक्ष) 2840/2011

26. लिखित बयान आज से तीस दिनों के भीतर दाखिल किया जाए। यदि कोई प्रतिवेदन हो तो उसे तीस दिनों के भीतर दाखिल किया जाए। पक्षकार, अपने पास और अपने अधिकार में मौजूद दस्तावेज उसी अवधि के भीतर दाखिल करेंगे।

27. दस्तावेजों की स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए मामले को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक 12.5.2014 को सूचीबद्ध किया जाए।

28. मामले को दिनांक 21.7.2014 को मुद्दे तय करने के लिए न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जब पक्षकार सुझाए गए मुद्दे न्यायालय के समक्ष लाएंगे।

न्या. जी.एस. सिस्तानी

10, मार्च 2014 एम.एस.आर.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।